



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1938 (श10)
(सं0 पटना 82) पटना, मंगलवार, 31 जनवरी 2017

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2017

सं0 ग्रा0वि0-14(विविध)न्याय-07/2015-298341—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 19529/2011 सदानंद यादव बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य बैच वार्दों में पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा जाँच अधिनियम 1952 (सं0- 60, 1952) की धारा-3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वर्ष 2002 से 2006 की अवधि में कार्यान्वित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के समापन के उपरांत अवशेष खाद्यान्न की क्षति के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण एवं उसके समतुल्य राशि की वसूली हेतु एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन अधिसूचना सं0 258459 दिनांक 18 जनवरी 2016 द्वारा किया गया। इस जाँच आयोग के कार्यकाल को छः माह की स्वीकृति पूर्व में सरकार के द्वारा दी गयी थी एवं अधिसूचना सं0-278503 दिनांक 18.07.2016 के द्वारा इसके कार्यकाल को छः महीने के लिए बढ़ाया गया था, जो कि दिनांक 17.01.2017 को समाप्त हो गया है।

आयोग के अनुरोध पर बिहार के राज्यपाल आयोग के कार्यकाल को छः माह यथा 18.01.2017 से 17.07.2017 तक विस्तारित करते हैं।

अधिसूचना सं0 258459 दिनांक 18 जनवरी 2016 एवं 278503 दिनांक 18 जुलाई 2016 के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा,
सरकार के अपर सचिव।

27 जनवरी 2017

सं० ग्रा०वि०-14(विविध)न्याय-07/2015-298341—का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा,
सरकार के अपर सचिव।

The 27th January 2017

No. ग्रा०वि०-14(विविध)न्याय-07/2015-298341—In compliance of the order passed by the Honorable High Court in the CWJC No. 19529/2011 Sadanand Yadav & Others Versus State of Bihar and Others and other batch cases, Government of Bihar vide notification no.- 258459 dated 18th January, 2016 decided to appoint a Judicial Commission of Enquiry for fixing the responsibility for the loss of residual food grain after the closing of Sampurn Gramin Rojgar Yojana and National Food for Work Scheme between 2002 to 2006, in exercise of powers conferred under Section 3(1) of the Commission of the Enquiry Act 1952 (No. 60, 1952). Earlier the government approved the tenure of the commission for six month and extended its tenure for another six month vide notification no. 278530 dated 18th July 2016, which is expired on 17.01.2017.

On the request of Commission the Governor of Bihar is pleased to extend the tenure for six month from 18.01.2017 to 17.07.2017.

The remaining parts of Notification no.- 258459 dated 18th January, 2016 and 278503 dated 18th July, 2016 will remain unchanged.

By the order of the Governor of Bihar,
RADHA KISHORE JHA,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 82-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>